सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-243 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, बुधवार 07 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

आज सायरन बजेगा फिर अँधेरा फैलेगा, देशभर में होगा मॉक ड्रिल

मुंबई,।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए तब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम और उच्चस्तरीय बैठकों को देखते हुए ऐसी संभावना है कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आ सकती है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आज बुधवार को देशभर में मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। आज 7 मई को देशभर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है।

मॉक ड्रिल

देश के कई राज्यो में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण मॉक ड्रिल के माध्यम से दिया जाएगा। मॉक ड्रिल में युद्ध जैसी स्थिति में हवाई हमले की स्थिति में सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाती है। मॉक ड्रिल के लिए चयनित स्थानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में देश भर के 13 शहर शामिल हैं। मुंबई, उरण, तारापुर को प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में देश भर के 21 स्थान शामिल हैं। इनमें ठाणे, पुणे, नासिक, रोहा-धताव-नागोठाणे, मनमाड, सिन्नर, थल-वायशेत, पिंपरी-चिंचवड़ शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में औरंगाबाद, भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग को शामिल किया गया है।

- 1971 में भी राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था

वर्ष 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। वरिष्ठ नागरिक अभी भी मुंबई शहर में सायरन बजने और यहां तक कि बिजली गुल होने के अनुभव बताते हैं। 1971 में दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया गया था। विभिन्न समाचार पत्रों ने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉक ड्रिल और युद्ध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में खबरें छापी थीं। सेना और जिला प्रशासन ने गांवों में मॉक ड्रिल कर अभ्यास किया था।

नागरिकों को क्या करना चाहिए?

क्या न करें?

- मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाया जा सकता है। यह सिर्फ एक अभ्यास है। इसलिए नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए। सायरन सुनते समय शांत रहें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- जैसे ही सायरन बजता है, तुरंत खुले क्षेत्र में चले जाएं। किसी सुरक्षित इमारत या बंकर में शरण लें। यदि आप बाहर हैं, तो पास की किसी इमारत में चले जाइये। सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। यदि आस-पास कोई बंकर उपलब्ध हो तो वहां जाएं।
- मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अध्ययन किया जाएगा। उस समय सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इससे दुश्मन देश के लिए नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर की खिड़कियों, दरवाजों और खिड़कियों को काले कपड़े से ढकें। घर के बाहर रोशनी न जाने दें। सड़क पर गाड़ी चलाते समय लाइटें बंद कर दें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों एवं विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमले से खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें और जानें कि आपातकाल में क्या करना चाहिए।
- मॉक ड्रिल में आपातकालीन निकासों का अध्ययन किया जाएगा। यह लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित स्थान पर जाते समय शांत रहें। अपने परिवार के साथ निकटतम सुरक्षित स्थान के बारे में पहले ही चर्चा कर लें।
- टी.वी., रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अफवाहों पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
- मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट के उपयोग के बारे में समझाया व समझाया जा सकता है। इसमें पानी, प्राथमिक चिकित्सा, टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां, अतिरिक्त कपड़े और कंबल शामिल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह किट आसानी से उपलब्ध हो।
- स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आप सिविल डिफेंस फोर्स या होमगार्ड से जुड़े हैं, तो अपनी जिम्मेदारी समझें और दूसरों की मदद करें। पड़ोसियों और आस-पास के लोगों के साथ समन्वय बनाए रखें। ताकि सभी सुरक्षित रहें।
- बच्चों को अभ्यास के बारे में जानकारी देते रहें। इसलिए अभ्यास के दौरान वे डरेंगे नहीं। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट प्रक्रियाओं के बारे में बताएं। बुजुर्गों और विकलांगों की मदद करें। ताकि वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें।
- सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से आने वाली खबरों पर भरोसा न करें। केवल सरकारी समाचार चैनलों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

जातीय पक्षपात पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला

छोटी जाति के जज की बर्खास्तगी से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।

न्यायपालिका में उपेक्षित समुदाय के जजों को भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की खंड पीठ ने पंजाब के एडिशनल सेशन जज की बर्खास्तगी के मामले में सुनवाई के दौरान कहा, जज को भी जातिगत पक्षपात का शिकार होना पड़ा। ऊंचे समुदाय के लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। झूठे आरोप में उसे बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जज की बर्खास्तगी को गलत मानते हुए जज को बहाल करने के आदेश दिए हैं। बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। उन्हें अमृतसर जिला कोर्ट में नियुक्त किया गया। इस दौरान दुष्कर्म के आरोप की शिकायत हाईकोर्ट में की गई। जब प्रेम कुमार वकालत करते थे। उसे वक्त उन्होंने दुष्कर्म पीड़ता की ओर से समझौते के लिए संपर्क कर पीड़ता को 1।50 लाख का मुआवजा दिलवाया था। इसकी शिकायत के आधार पर जज प्रेम कुमार की हाई कोर्ट द्वारा जांच कराई गई। उनकी ईमानदारी को संदिग्ध मानते हुए 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने शिकायत के आधार पर प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने निर्णय उनकी बर्खास्तगी को गलत बताते हुए जज की बहाली करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। ऊंचे समुदाय के लोग उपेक्षित समुदाय के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देश में जब एक जज के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है,कि आज भी देश में उपेक्षित वर्ग का किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है।

पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 244 जगह मॉक ड्रिल

सिखाए जाएंगे हमले से बचने के तरीके, टॉर्च-कैश रखने की सलाह

नई दिल्ली।

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटगरी-1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी-3 कम सेंसेटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई हाईलेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे।

कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी कहा- 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा हटाएं

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार के जातिगत गणना के फैसले से कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि उसकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने देशभर में चलने वाली इस कवायद को लेकर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू करने की अपील की है। पीएम मोदी को उन्होंने इस काम के लिए कांग्रेस शासित तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है। खरगे ने अपने पत्र में कहा है कि राज्यों की ओर से पारित आरक्षण को तमिलनाडु की तर्ज पर संविधान की नौंवी अनुसूची में डाला जाए, आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के बड़े मकसदों को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना के सवालों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए, जिससे हर जाति के सामाजिक और आर्थिक हालात का सही आकलन हो सके और उनके संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया जा सके। पीएम मोदी को लिखे पत्र में खरगे ने कहा, 'मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना कराने की मांग आपके समक्ष रखी थी। अफ़सोस की बात है कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। दुर्भाग्य से, उसके बाद आपके पार्टी के नेताओं और खुद आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार हमले किए।' उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह मांग गहन सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तीकरण के हित में है।' पत्र में कहा गया है, आपने बिना किसी स्पष्ट

विवरण के यह घोषणा की है कि अगली जनगणना (जो वास्तव में 2021 में होनी थी) में जाति को भी एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया जाएगा। खरगे ने कांग्रेस शासित तेलंगाना में हुए जातिगत सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा, 'जनगणना से सम्बंधित प्रश्नावली का डिजाइन बेहद महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में तेज हवाओं से ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे

मप्र में ओले गिरने की चेतावनी, 27 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली/भोपाल/लखनऊ।

मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश-हरियाणा सहित देश के 27 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं, हिमाचल में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसके कारण कई शहरों में पारा 8 डिग्री से 10 डिग्री तक गिर गया है। गुना में तेज आंधी के चलते शादी का टेंट उड़ गया। अशोकनगर में मोबाइल टावर धाराशायी हुआ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को आंधी के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहा। अलीगढ़ में तेज आंधी के बीच बच्चे को बचाने निकली मां की टीनशेड से कटकर गर्दन कट गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया। इधर, राजस्थान के कई जिलों में रविवार रात से आंधी-तूफान के साथ बारिश जारी है। पाली में आंधी से चलती ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरकर हाईटेंशन बिजली के खंभे से टकरा गए। बूंदी जिले में ट्रांसफॉर्मर जेसीबी मशीन पर गिर गया। भीलवाड़ा-पाली में बारिश के साथ ओले गिरे। आज 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

देश के सबसे बड़े जज के पास कितनी संपत्ति

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का भी ब्यौरा दिया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास 2015 मॉडल की स्विफ्ट कार है। जानते हैं इनके पास कुल कितनी संपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी के तहत ऐतिहासिक फैसला लिया है। जनता का विश्वास जुडिशियरी पर और बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारत में ऐसा पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक की गई है। हालांकि 33 न्यायाधीशों में से 22 के संपत्ति की जानकारी को देखा जा सकता है। बाकी के सभी जजों ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और बीस अन्य न्यायाधीशों के संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिनमें वे तीन न्यायाधीश भी शामिल हैं जो आने वाले समय में सीजेआई बनने की कतार में हैं। यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक परिसर से नोटों की बरामदगी को लेकर विवाद के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास साउथ दिल्ली में तीन बेडरूम वाला डीडीए फ्लैट, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में दो पार्किंग स्पेस के साथ चार बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2446 वर्ग फीट है। गुरुग्राम के सेक्टर 49 के सिसपाल विहार में चार बेडरूम वाले फ्लैट में 56 प्रतिशत हिस्सा, जिसका सुपर एरिया 2016 वर्ग फीट है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में जमीन में अविभाजित हिस्से के साथ घर के आंशिक मालिक देव राज खन्ना (एचयूएफ) में हिस्सा है।

आतंकियों का छिपाया विस्फोटक पकड़ा

आरपीजी-आईईडी, वायरलैस सेट, ग्रेनेड मिले

अमृतसर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। खुफिया इनपुट के बाद अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल केंद्रीय एजेंसी के साथ तिब्बा नंगल-कुलार रोड के पास बने जंगल में पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री मिली।पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने पंजाब में छिपे अपने स्लीपर सेल को दोबारा एक्टिव करने की प्लानिंग बनाई थी। विस्फोटक सामग्री की बरामदगी इसी साजिश का हिस्सा है। आतंकियों ने ये सामग्री भविष्य में आतंकी घटनाओं के लिए छिपाकर रखी थी। इसे लेकर अमृतसर एसएसओसी की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रूस से इसी महीने आ जाएगा जंगी जहाज तमल

नई दिल्ली।

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं के बीच भारत की समुद्री ताकत बढ़ने वाली है। रूस में बने एक मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को मई के अंत (28 मई) में सौंपा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तमल युद्धपोत 2016 में हुए भारत-रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत चार तलवार-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से दो रूस के यंतर शिपयार्ड में और दो भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तमल रूस में बनने वाला दूसरा फ्रिगेट है। इससे पहले ब्रह्मोस् तुशिल को दिसंबर 2024 में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया था।

पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी में भारत

नई दिल्ली।

सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी की है। खबर है कि भारत वर्ल्ड बैंक और एक्सपर्ट मिशेल लीनो को बैठकों में शामिल नहीं होने के अपने फैसले के बारे में जानकारी देने वाला है।

कहा जा रहा है कि भारत लीनो से आगामी बैठकों को होल्ड या स्थगित करने के लिए कह सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अप्रैल में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। सरकार ने भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 करने, पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देने समेत कई कदम उठाए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि संधि के स्थगित होने के कारण सरकार लीनो के दफ्तर को आगामी बैठकों पर रोक लगाने के लिए कह सकती है। खास बात है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लीनो का दफ्तर नवंबर में विएना में बैठक करने जा रहा था।

खास बात है कि पीसीए ही पाकिस्तान की तरफ से किशनगंगा और रतले बांध को लेकर उठाए गए विवाद का निपटारा कर रहा है।

एक जानकार ने बताया, चूंकि संधि स्थगित हो चुकी है, तो संधि के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट विवाद के समाधान में शामिल नहीं होंगे। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित करने का ऐलान किया था।

इस बार बाबा बर्फानी की 7 फीट ऊंची शिवलिंग, 3 जुलाई से होगी यात्रा शुरु

लाखों लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी

श्रीनगर।

अमरनाथ की गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा बना है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी जो करीब 38 दिन तक चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यह यात्रा पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं नजर आ है।

अब तक पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए करीब 3.50 लाख श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन कराया है। श्राइन बोर्ड ने ई-केवॉयसी, आरएफआईडी कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का फैसला लिया गया है, ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ यहां आ सकते हैं, इसलिए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है।

पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अब टट्टूवाले और स्थानीय सेवादार बेस

कैंप में आईडी जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सख्त आईडी वैरिफिकेशन प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर- रोशनी जिनके साथ चलती थी

(लेखक - ललित गर्ग)

(रवीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती - 7 मई, 2025)

भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बाँग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांङ्ला' के रचयिता एवं भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती हर साल 7 मई को मनाई जाती है। वे एक महान एवं विश्वविख्यात कवि, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्हें बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नयी जान फूँकने वाले युगदृष्टा, युगस्रष्टा एवं युग-निर्माता माना जाता है। रवीद्रनाथ टैगोर को उनकी अनूठी, हृदयस्पर्शी एवं आध्यात्मिक रचनाओं के लिए लोग गुरुदेव कहकर पुकारते हैं। उनका जन्मदिन केवल जन्म का जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके विचारों और मूल्यों को याद करने और उनके सद्भाव, संपूर्णता और अखंडता के आदर्शों और आकांक्षाओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करने का भी एक अवसर है। टैगोर एक ऐसे दिव्य एवं अलौकिक व्यक्ति एवं समाजक्रांति के प्रेरक थे, रोशनी जिनके साथ चलती थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। उनकी आरम्भिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया फिर लन्दन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया किन्तु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश लौट आए। सन् 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया; बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थीं। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ, संगीतकार और नाटककार थे एवं इनकी बहिन स्वर्णकुमारी उपन्यासकार थी। टैगोर ने लगभग 2,230 गीतों की रचना की। रवींद्र संगीत बाँग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं एवं संवेदनाओं के अलग-अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव टैगोर की कविताओं में हमें अस्तित्व के असीम सौन्दर्य, प्रकृति और भक्ति के दर्शन होते हैं। उनकी बहुत-सी कविताएं प्रकृति के सौन्दर्य से जुड़ी हैं। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लान्ति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी सम्पर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग-अलग रूपों में उभरकर सामने आया। टैगोर और महात्मा गाँधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। एक समय था जब शान्ति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे, उस समय गांधीजी ने टैगोर को एक बड़ी राशि का अनुदान का चेक दिया था। टैगोर के कई गीतों और कहानियों ने मानव चेतना को बदलने और कार्य करने के लिए साहस और प्रतिबद्धता को प्रेरित किया। उन्होंने कला का अभ्यास कला के लिए नहीं किया, न ही आत्म-अभिव्यक्ति के तरीके के रूप में और कम से कम मनोरंजन के लिए तो कतई नहीं किया, बल्कि उनकी कला भी नये मानव एवं नये विश्व की संरचना से प्रेरित थी। उनकी कला जीवन के गहरे अर्थ को स्पष्ट करने और आत्मा को ठीक करने की पेशकश थी।

अपने शिल्प के उस्ताद के रूप में, टैगोर ने कविता की शुद्धता को जीने के उद्देश्य के साथ जोड़ा। उन्होंने न केवल अपने जीवन में मृत्यु, अवसाद और निराशा के कारण अनुभव किए गए दुख और पीड़ा को ठीक किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के भीतर अन्याय और असमानता के घावों को भरने के लिए भी काम किया। उन्होंने उन्नत कृषि, अच्छे स्कूलों, आरामदायक आर्थिक स्थितियों और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से मानव समुदायों के बाहरी विकास के लिए काम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने आत्मा के नवीनीकरण, आत्मा की देखभाल, हृदय को पोषण और कल्पना को पोषित करने के माध्यम से आंतरिक विकास पर जोर दिया। वे एक ऐसे पुरुषार्थी पुरुष का महापुरुष के रूप में जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने हर इंसान के महान् बनने का सपना संजोया और उसके लिये उनके हाथ में सुनहरे सपनों को साकार होने की जीवनशैली भी सौंपी।

अपने शिल्प के उस्ताद के रूप में, टैगोर ने कविता की शुद्धता को जीने के उद्देश्य के साथ जोड़ा। उन्होंने न केवल अपने जीवन में मृत्यु, अवसाद और निराशा के कारण अनुभव किए गए दुख और पीड़ा को ठीक किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के भीतर अन्याय और असमानता के घावों को भरने के लिए भी काम किया। उन्होंने उन्नत कृषि, अच्छे स्कूलों, आरामदायक आर्थिक स्थितियों और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से मानव समुदायों के बाहरी विकास के लिए काम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने आत्मा के नवीनीकरण, आत्मा की देखभाल, हृदय को पोषण और कल्पना को पोषित करने के माध्यम से आंतरिक विकास पर जोर दिया।

टैगोर गहन आध्यात्मिक एवं साधक पुरुष थे, उन्होंने अध्यात्म के गहन रहस्यों को उद्घाटित किया। उनके अनुसार मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी भी रूप में कमजोर नहीं होती, बस उसे समझने वाला चाहिए। जिस प्रकार शब्दों की भाषा का शास्त्र होता है, उसी प्रकार मौन का भी भाषा विज्ञान होता है। मौन को समझा तो जा सकता है, पर समझाया नहीं जा सकता। संभवतः इसीलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मौन अनंत की भाषा है। टैगोर अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वयक थे। टैगोर ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भौतिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता व्यक्त की। एक के बिना दूसरा एक पैर पर चलने जैसा है। वे आध्यात्मिक-वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण के प्रेरक थे। इस संतुलित और समग्र विश्वदृष्टि की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और लचीले भविष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता एवं शर्त है।

शुद्ध तर्क और शुद्ध भौतिकवाद उतने ही विनाशकारी हैं, जितने कि विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मोक्ष की खोज। टैगोर ने विज्ञान और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करते हुए शब्दों और कर्मों में शाश्वत ज्ञान और कालातीत मूल्यों को व्यक्त किया। टैगोर का विश्वदृष्टि तर्क और धर्म, आत्मा और पदार्थ की एकता को देखना और उन्हें एक साथ नृत्य करने देना है। यह एक बड़ी दृष्टि है जहाँ विज्ञान आध्यात्मिकता का पूरक है, कला पारिस्थितिकी का पूरक है और स्वतंत्रता समानता का पूरक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हमें नस्ल, रंग, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा और राष्ट्र की अपनी क्षुद्र पहचान से ऊपर उठने और अपनी सामान्य मानवता के साथ पहचान बनाने का आग्रह किया। उन्होंने मानवता की एकता और स्वतंत्रता, न्याय और शांति के सर्वोपरि महत्व की घोषणा करते हुए अमेरिका से रूस, चीन से अर्जेंटीना तक समूचे विश्व की अथक यात्रा की। उन्होंने अपने लाखों देशवासियों को अपने संकीर्ण स्वार्थ को त्यागने और राष्ट्रीयता, समानता, एकजुटता और नैतिकता को अपनाने के लिए अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आत्म-भोग को त्याग दिया और सामाजिक विभाजन को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। विशेष रूप से उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को भरने की कोशिश की। रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रेरणाएं इतनी विविधमुखी थी कि उनसे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। चाहे वह आपसी संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो या राजनीतिक संबंध हो- हर तरह के जीवन को उन्होंने प्रेरक बनाने का उपक्रम किया। वे कभी घटना से, कभी शब्दों से, कभी क्रिया से, कभी पत्रों से, तो कभी किसी उदाहरण या संस्मरण से व्यक्ति की चेतना को झकझोर कर आदर्श और ज्ञान के प्रति अनुराग और जोश जगाते थे।

वे इस कला में निष्णात थे कि कब किसको किन शब्दों में उचित प्रेरणा दी जाए। रवीन्द्रनाथ टैगोर के पुरुषार्थी जीवन की एक पहचान थी गत्यात्मकता। वे अपने जीवन में कभी कहीं रुके नहीं, झुके नहीं। प्रतिकूलताओं के बीच भी अपने अपने लक्ष्य का चिराग सुरक्षित रखा। इसलिए उनकी हर सांस अपने दायित्वों और कर्तव्यों पर चौकसी रखती थी। खून पसीना बनकर बहता था। रातें जागती थी। दिन संवरते थे। प्रयत्न पुरुषार्थ बनते थे और संकल्प साधना में ढलते थे। यही कारण है कि आज उनके प्रयत्नों से न केवल भारतीय समाज बल्कि विश्व मानवता का जीवन प्रेरक बना है, सार्थक बना है और वे सभी उस महामानव को तहेदिल से याद करते हैं।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

गरीब की दवा

कई बार समाचार सुनने-पढ़ने को मिलते हैं कि परिजनों के गंभीर व असाध्य रोगों के महंगे इलाज की वजह से लाखों लोग गरीबी की दलदल में डूब गए। कोरोना संकट के दौरान भी लोगों द्वारा घर, जमीन व जेवर बेचकर अपनों की जान बचाने की कोशिश की खबरें मीडिया में तैरती रही। लेकिन सामान्य दिनों में दवा कंपनियों की मिलीभगत व दबाव में लिखी जाने वाली महंगी दवाइयां भी गरीबों को टीस दे जाती हैं। इसके बावजूद कि बाजार में उसी साल्ट वाली गुणवत्ता की जेनेरिक दवा सहज उपलब्ध है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से जेनेरिक दवाइयां लिखने की अनिवार्यता के निर्देश का अच्छा-खासा विरोध हुआ, जिसके चलते निर्णय वापस लेना पड़ा था। अब इसी चिंता को देश की शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्त किया है। दरअसल, बीते शुक्रवार को दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी के कारोबार से बढ़ती दवाओं की कीमतों के बाबत एक मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखना प्रारंभ कर दें, तो दवा कंपनियों व चिकित्सकों के अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। निस्संदेह, तरह-तरह के प्रलोभन व परोक्ष-अपरोक्ष लाभ देकर दवा कंपनियां चिकित्सकों पर महंगी दवा लिखने का दबाव बनाती हैं। जिसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है, जो महंगी दवा खरीदने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे में वे कर्ज लेकर या अपने रिश्तेदारों से मदद लेकर किसी तरह गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज कराते हैं। इस खर्च के दबाव के चलते परिजनों को भी तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। गाहे-बगाहे सरकारों ने दवा कंपनियों की बेलगाम मुनाफाखोरी रोकने को कदम उठाने की घोषणाएं तो कीं, लेकिन समस्या का सार्थक समाधान नहीं निकल पाया। चिकित्सा बिरादरी की तरफ से भी यदि इस दिशा में सहयोग मिलने लगे तो इस समस्या का समाधान किसी सीमा तक संभव हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक संकट यह भी है कि दवा कंपनियों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जेनेरिक दवाइयां रोग के उपचार में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होती। निस्संदेह, सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन देने के उसके प्रयास क्यों सिरे नहीं चढ़ते। एक वजह यह भी है कि दवा कंपनियों की लॉबी खासी ताकतवर होती है और साम-दाम-दंड-भेद की नीति का उपयोग करके अपने उत्पादों का विपणन करने में सफल हो जाती है। ऐसे आक्षेपों से चिकित्सा बिरादरी भी दोषमुक्त नहीं हो सकती, जो दवा कंपनियों के लोभसंवरण से मुक्त नहीं हो पाती। सरकारों को देखना चाहिए कि दवा कंपनियों द्वारा पोषित कदाचार पर नियंत्रण के प्रयास जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाते। यदि ये कदम सख्ती से उठाए जाएं तो गरीब मरीज गंभीर रोगों का उपचार करने में सक्षम हो पाएंगे। फिर उनके अपनों का इलाज उनकी क्षमता के अनुरूप हो सकेगा। निस्संदेह, लंबे उपचार व असाध्य रोगों के इलाज में दवाओं की कीमत एक प्रमुख घटक होता है। यदि दवा नियंत्रित दामों में मिल सके तो उनकी बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। निस्संदेह, दवाओं की कीमत हमारी चिकित्सा सेवाओं के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

नशा मुक्त मारवाड़ की ओर - परंपरा का नवोदय

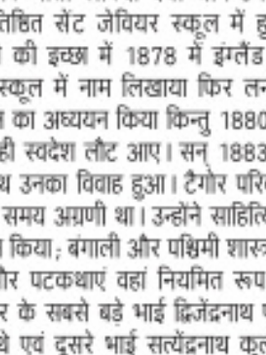

लेखाराम बिश्नोई
लेखक विचारक

पश्चिमी राजस्थान, विशेषतकर मारवाड़, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, शौर्य गाथाओं और रंगीनी जीवनशैली के लिए विख्यात रहा है। यहां की 'मनवार' परंपरा, जिसमें प्रेमपूर्वक लोगों को आमंत्रित कर पकवानों से स्वागत किया जाता है, हमारी सभ्यता की पहचान है। किंतु वर्तमान समय में यह गौरवशाली परंपरा नशे की बुराई से प्रभावित हो रही है, जहाँ अफीम और डोडा चूरा जैसे पदार्थों ने मनवार को विकृत कर दिया है। नशा न तो हमारे गौरवशाली अतीत की कोई गाथा है, और न ही यह हमारे सपनों के उज्ज्वल भविष्य की कोई तस्वीर। यह तो हमारे वर्तमान पर पुती वह कालिख है, जो हमें अंधकार की ओर ले जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस कालिख को यत्नपूर्वक साफ करें, ताकि वर्तमान की चमक से हमारा भविष्य स्वर्णिम बन सके।

आज का समाज प्रगति की ओर तो बढ़ रहा है, परन्तु नशाखोरी जैसी बुराइयाँ उसकी जड़ें खोखली कर रही हैं। यह एक ऐसा दलदल है, जिसमें एक बार फँस जाने पर निकल पाना कठिन हो जाता है। युवावर्ग, जो किसी भी राष्ट्र की नींव होता है, सबसे अधिक इसकी चपेट में है। दुर्भाग्यवश, कई स्थानों पर नशे को परंपरा और सामाजिक रीतियों से जोड़ दिया गया है। इसे 'मनुहार' का नाम देकर सामाजिक स्वीकार्यता दी जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

क्या यह हमारे पूर्वजों के मूल्यों का अपमान नहीं है? जिन्होंने संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण को जीवन का आधार माना — आज उनके नाम पर नशे को बढ़ावा देना उनके आदर्शों की अवहेलना है।

हमें चाहिए कि वर्तमान की प्रत्यंचा को अतीत की जड़ों से जोड़ते हुए उसे भविष्य की दिशा में खींचें। यह तभी संभव है जब हम नशाखोरी जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और समाज को भी जागरूक करें। परिवार, विद्यालय और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्ग दिखाएँ।

सरकार को भी कठोर कदम उठाने होंगे — नशे के व्यापार को रोकना, जनजागरूकता अभियान चलाना, नशा किसी भी रूप में हमारे समाज के लिए घातक है। यह न तो हमारी संस्कृति है, न परंपरा और न ही शान।

आज आवश्यकता है कि हम सभी सज्जन शक्ति एकजुट होकर यह संकल्प लें - 'ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे।' अपने हाथों से इन नशे के पदार्थों को गिराकर, अपने हाथों में पवित्र जल लेकर यह शपथ लें, कि हम अपने घर, समाज और आने वाली पीढ़ियों को इस बुराई से बचाएंगे।

हमें फिर से अपनी परंपरा को उसकी मूल भावना के साथ जोड़ने में प्रशासन काफी सक्रिय हो रहा है। विशेष कर जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने इस अभियान को जन-सामान्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब समय है कि हमारी मनवार में लौंग, इलायची, मेवा, मिश्री, फल, मिष्ठान्न और पकवान हों - न कि मौत के समान नशीले पदार्थ। जब हम इस सांस्कृतिक परिवर्तन को अपनाएंगे, तब ही हम नशा मुक्त मारवाड़ और नशा मुक्त राजस्थान की ओर एक ठोस कदम बढ़ा पाएंगे।

हमारी जुबान पर जुहार होगी, दिल में गुहार होगी और समाज में मनवार होगी - लेकिन वह मनवार, जो जीवन को संजीवनी दे, उसे मृत्यु की ओर न धकेले। यह केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति होगी। यदि हम आज नशे की इस विषबेला को नहीं काटेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी इससे जड़ से ग्रसित हो जाएगी।नशा किसी भी रूप में हमारे समाज के लिए घातक है। यह न तो हमारी संस्कृति है, न परंपरा और न ही शान। यदि हम एक स्वच्छ, सशक्त और उज्ज्वल समाज का सपना देखते हैं, तो सबसे पहले हमें नशे की इस कालिख को मिटाना होगा। तभी हमारे वर्तमान की चमक, भविष्य को स्वर्णिम बना सकेगी।

आइए, आज ही यह प्रण लें कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाएंगे, उसे पुनः गौरवशाली बनाएंगे और नशे को सदा के लिए अलविदा कहकर स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध मारवाड़ की ओर कदम बढ़ाएंगे।

लेखाराम बिश्नोई
लेखक, विचारक सामाजिक कार्यकर्ता

(चिंतन-मनन)

भय को निकालें

जब क्रियता का संवेदन होता है तो अक्रियता का संवेदन भी होगा। हमारे सारे तनाव इस परिधि में हो रहे हैं। क्रियता का संवेदन हो, क्रिय मिले, क्रिय को वियोग न हो और अप्रियता का योग न हो। बस, सारी तनाव की यह सीमा है। इसी सीमा में सारे तनाव प्रकट हो रहे हैं। पर मूल में जो छिपा हुआ कारण कार्य कर रहा है, वह मात्र एक ही है- प्रियता का संवेदन, अप्रियता का संवेदन। अब यह संवेदन है तो भय भी पैदा होगा।

एक छोटी सी कहनी है। एक आदमी बहुत डरता था। वह समझदार आदमी के पास गया जो मंत्र को जानता था। उसके पास जाकर बोला, मुझे डर बहुत लगता है। उसने ताबीज बना दिया और कहा, इसको बांध लो। तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। ताबीज बांध लिया। डर लगना कम हो गया। पर मंत्र जानने वाला व्यक्ति कुछ दिन बाद ही आया और पूछा- भाई! अब डर तो नहीं लगता? उसने कहा, जो काल्पनिक था, वह तो नहीं लगता किन्तु एक डर और पैदा हो गया। निरन्तर मन में भय बना रहता है कि कहीं ताबीज गुम न हो जाए। एक भय तो समाप्त हुआ, दूसरा भय और आ गया।

जब यह दृष्टि मूल में बनी रहती है कि प्रिय का वियोग न हो जाए, अप्रिय का योग न हो जाए, तब भय अनिवार्य है। उस मूल कारण से तनाव पैदा होता है। जब प्रिय संवेदन की भावना है, उसका तनाव भी पैदा होता है। हमारे जीवन के संचालन के केन्द्र में जो तत्व है, वह है लोभ। मनोविज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां होती हैं। जीने की इच्छा भी इसी में एक है।

विचार मंथन

माक ड्रिल को लेकर मीडिया की सक्रियता

(लेखक- सनत जैन)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। इसको देखते हुए 1971 के बाद पहली बार देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। 7 मई को देश के अधिकांश जिलों में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में हवाई हमले की चेतावनी सायरन के माध्यम से दी जाएगी। इस चेतावनी का मुकाबला नागरिकों को किस तरह से करना है। इसकी जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को भी इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। हवाई हमले की स्थिति में तुरंत किस तरह से ब्लैक आउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों को किस तरीके से छुपाया जाएगा। हवाई हमले से यदि कोई नुकसान होता है, तो निकासी की क्या व्यवस्था होगी। सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी। इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक जिले के अग्निशमन विभाग के अधिकारी किस तरह से राहत पहुंचाने का काम करेंगे, नियंत्रण कक्ष किस तरह से लोगों को सूचना देंगे और उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। युद्ध की स्थिति में बंकरों और खाइयों का निर्माण सीमावर्ती जिलों में किस तरह से किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण युद्ध की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की योजनाओं को किस तरह से संचालित किया जाना है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस और संबंधित एजेंसियों को पूर्व अभ्यास कराया जाएगा। 1971 के बाद कभी भी भारत में इस तरीके की स्थिति नहीं बनी थी। 2025 में युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति और महत्वपूर्ण स्थलों को बचाने के लिए यह प्रशिक्षण जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 7 मई का दिन निश्चित किया है। जब देशभर के अधिकांश जिलों में विशेष रूप से जो पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं। उन राज्यों के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हैं, उसको देखते हुए यह सतर्कता जरूरी थी। 55 साल की उम्र तक के लोगों ने युद्ध में किस तरह से बचाव करना होता है, यह उनकी जानकारी में नहीं है। जो लोग 55 साल की उम्र से ज्यादा के हैं उन्होंने जरूर 1962, 1965 और 1971 के दौरान हुए युद्ध में युद्ध के दौरान किस तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसकी जानकारी उन्हें है। केंद्र सरकार ने जो प्रशिक्षण देने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह सतर्कता नागरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से इस मॉक ड्रिल का टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर एक धारणा यह भी बनने लगी है। युद्ध के दौरान कोई भी देश इस तरह के प्रचार-प्रसार से बचता है। भारत का नेशनल मीडिया सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को जिस तरह से टेलीविजन चैनल में कर रहा है, यदि युद्ध होता है तो उससे भारत को नुकसान होना तय है। भारत का नेशनल टेलीविजन मीडिया जिस तरह से तकनीकी युद्ध में उपयोग आने वाले उपकरण, सैन्य सामग्री और किस तरह की व्यवस्था सेना द्वारा की गई है, उसको सार्वजनिक किया जा रहा है।. यह स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली है। जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी जानकारी को छुपाते हैं। युद्ध की दशा में हम दुश्मन देश के ऊपर किस तरह से वार करेंगे और किस तरह से युद्ध में अपनी सुरक्षा करेंगे, इसका प्रचार-प्रसार इसके पहले कभी नहीं हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है। नेशनल टेलीविजन मीडिया जिस तरह से मॉक ड्रिल का प्रोपेगेंडा कर रहा है, युद्ध के समय हम देश की आंतरिक स्थितियों को सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में घर बैठे दुश्मन देश को उपलब्ध करा रहे हैं। इससे युद्ध के दौरान भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस दिशा में टेलीविजन मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। टेलीविजन मीडिया जिस तरह से दुश्मन देश को भारत की आंतरिक जानकारी देते हुए बड़े-बड़े दावे कर रहा है। यह देश के हित में नहीं है। इस बात

का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है तो नेशनल टेलीविजन मीडिया का यह कृत्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। सरकार यदि दुश्मन देश को डराने के लिए इस तरह का प्रचार-प्रसार करा रही है, तो बात अलग है। करीब 55 साल के बाद भारत में युद्ध की स्थिति बनी है। ऐसी स्थिति में हमें सभी मोर्चे पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। जनता भी युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे तरीके से कर पाए, इसके लिए आम नागरिकों को भी प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। अनावश्यक प्रचार-प्रसार से बचा जाना चाहिए, वर्तमान स्थिति में यही कहा जा सकता है।

टैरिफ और दुनिया में जारी तनाव से बढ़ी व्यापार अनिश्चितता, मूडीज ने जारी किया अनुमान

भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था होगी डांवाडोल

नई दिल्ली।

इस साल भारत सहित दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 के लिए जो अनुमान जारी किया है वह चिंताजनक है। मूडीज के अनुमान के अनुसार, इस साल भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डांवाडोल होगी। यानी पूर्व में जो अनुमान किए गए हैं वे फेल हो सकते है। दरअसल, अमेरिका द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से वैश्विक स्तर पर व्यापार अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर भारत की वृद्धि दर पर भी पडने की आशंका है। यही वजह है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज ने पहले अनुमान जताया था कि 2025 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। मूडीज ने अपने वैश्विक मैक्रो आउटलुक 2025-26 में मई अपडेट में बताया है कि भूराजनैतिक परिस्थितियों जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से भी भारत की विकास दर पर असर पडने की आशंका है।

इससे निवेश और उद्योगों पर असर आएगा। हालांकि मूडीज ने साल 2025 के लिए भले ही विकास दर में कटौती का अनुमान जताया है, लेकिन साल 2026 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत ही रहने की संभावना जताई है। साल 2024 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रही थी।

मूडीज ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंचमार्क नीतिगत दरों को कम करेगा। अमेरिका चीन की वृद्धि दर का अनुमान भी घटाया मूडीज ने कहा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जारी टैरिफ युद्ध के असर से पूरी दुनिया में व्यापार और निवेश पर असर आएगा। इसके चलते वैश्विक विकास दर इस साल धीमी रहने का अनुमान है। मूडीज ने अमेरिका के जीडीपी वृद्धि अनुमान को भी कम किया है। मूडीज के तहत 2025 में अमेरिका की वृद्धि दर एक प्रतिशत रह सकती है, जिसके पहले दो प्रतिशत रहने का अनुमान था। वहीं अगले साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत रह सकती है, जिसके लिए पहले 1.8 प्रतिशत का अनुमान था। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में 3.8 प्रतिशत और 2026 में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2024 में पांच प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है।

संक्षिप्त समाचार

सरकार चाहती है सीबीआई निदेशक सूद का कार्यकाल बढ़े, राहुल गांधी सहमत नहीं

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार वर्तमान में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह कदम बिना किसी विरोध के नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रस्तावित विस्तार का विरोध करते हुए औपचारिक रूप से असहमति पत्र पेश किया है। इससे पहले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। शाम को पीएमओ में हुई बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने मौजूदा निदेशक के लिए एक साल का विस्तार देने पर जोर दिया। यह बैठक मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के दो साल का कार्यकाल 25 मई को पूरा होने से कुछ दिन पहले हुई। 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद अपनी नियुक्ति से पहले दक्षिणी राज्य के डीजीपी थे। उन्होंने 25 मई, 2023 को सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाला था। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं।

तनाव के बीच एलओसी पर पकड़ाया पाकिस्तानी युवक, सेना ने बढ़ाई चौकसी

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी से एक पाकिस्तानी नागरिक को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट में एक सेना के अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सैनिकों की तैनाती की गई है। इससे पहले रविवार रात को बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसने के बाद एक 24 साल के पाकिस्तानी युवक को हिरासत में लिया था, जिसकी बाद में पहचान पाकिस्तान के गुजरांवाला के हुसैन के रूप में हुई। अधिकारियों ने कहा कि युवक के पास से पाकिस्तानी मुद्रा और एक राष्ट्रीय पहचान पत्र बरामद किया गया है। उसे शुरुआती पूछताछ के लिए सीमा चौकी पर लाया गया और आगे की जांच अभी चल रही है।

बीजेपी प्रभारी अब प्रवासी बिहारियों से संपर्क कर वोट डालने की करेंगे अपील

पटना।

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों, प्रदेश प्रवक्ता और पदाधिकारी के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और दुष्यंत गौतम ने की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी ने अब तक पूरे देश में 150 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी 150 जिलों के प्रभारी को अपने क्षेत्र में भेजा जाएगा। वहां रह रहे प्रवासी बिहारियों से सभी प्रभारी सीधा संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य भावनात्मक जुड़ाव बनाना और उन्हें बिहार आकर मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा।

भारत ने किया पानी के नीचे 'नौसैनिक सुरंग' का सफल परीक्षण

नई दिल्ली।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। एमआईजीएम, एक उन्नत अंडरवाटर नेवल माइन है, जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा पुणे में डीआरडीओ की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया था। भारत ने आधुनिक जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ अपनी नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने डिजाइन की गई पानी के नीचे 'नौसैनिक सुरंग' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 'मल्टी-इंफ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया।

पंजाब के जंगलों में आतंकियों ने छिपाई विस्फोटक सामग्री, पुलिस ने की बरामद

डीजीपी ने कहा- स्लीपर सेल को सक्रिय करने आईएसआई ने बनाई योजना

अमृतसर।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। खुफिया इनपुट के बाद अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल केंद्रीय एजेंसी के साथ तिब्बा नंगल-कुलार रोड के पास बने जंगल में पहुंची। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री मिली। पंजाब के डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने पंजाब में छिपे अपने स्लीपर सेल को दोबारा सक्रिय करने की योजना बनाई थी। विस्फोटक सामग्री की बरामदगी इसी साजिश का हिस्सा है। आतंकियों ने ये सामग्री भविष्य में आतंकी घटनाओं के लिए छिपाकर रखी थी। इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सोमवार को गुरदासपुर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। उसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी मिला है। आईकार्ड पर युवक का नाम हुसनैन लिखा है। वह पाकिस्तान में गुजरांवाला का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अनजाने में भारतीय सीमा में आ गया। बीएसएफ को उससे कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। बीएसएफ ने उसको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि किसी संभावित साजिश या सुरक्षा चूक की आशंका की गंभीरता से जांच की जा सके।

सीजेआई संजीव खन्ना ने 406 जजों की सिफारिश की

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी रिटायरमेंट से पहले उन 406 नामों की लिस्ट भी जारी कर दी है जो कोलेजियम के लिए केन्द्र सरकार को भेजे थे। इसमें से 221 उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और बाकी या तो वेटिंग लिस्ट में हैं या फिर उन उम्मीदवारों के नाम को खारिज कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जिन उम्मीदवारों के नाम को कोलेजियम के लिए भेजा उसमें कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपनी रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए की गई सिफारिशों का डिटेल को पब्लिक कर दिया है। इसमें 9 नवंबर 2022 से 5 मई इस साल तक की सभी सिफारिशों को शामिल किया है जिसमें जाति, लिंग और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार या परिवार से है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार, कोलेजियम द्वारा सरकार को सिफारिश किए गए 406 उम्मीदवारों में से 221 को सरकार ने मंजूरी दी है, जबकि बाकी नाम या तो वेटिंग लिस्ट में है या उन्हें खारिज कर दिया गया है।

डेटा से पता चलता है कि 406 में से केवल 34 महिलाएं थीं। केवल आठ उम्मीदवार अनुसूचित जाति से थे। 7 अनुसूचित जनजाति से थे। 32 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। 7 पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग से थे और 14 उम्मीदवार मौजूदा या रिटायर जजों से संबंधित थे। नियुक्तियों पर अतिरिक्त डेटा का खुलासा करने का निर्णय सभी 31 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने के एक महीने बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मई को रिटायर हो रहे हैं।

भारत और रुस के मजबूत संबंध नेहरु और इंदिरा की देन, इसलिए आज भी रुस है भारत के साथ खड़ा

कांग्रेस नेता श्रीनेत ने कहा- यह देश की पिछली सरकार की विदेशी नीति का नतीजा

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पीएम नरेन्द्र मोदी को फोन करने के बाद भारत के रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों की नींव रखने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया है। श्रीनेत ने कहा कि आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह हर सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का नतीजा है और इसकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं और यह पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की ही देन है। श्रीनेत ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और मौजूदा तनाव को राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक व्यापक लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मानवता और अमानवीयता की लड़ाई है। पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहता है। पीएम मोदी को ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बता दें सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें भारत में आयोजित होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।

नदी सफाई प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला, मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी

ठेकेदारों और बीएमसी अफसरों के घर-दफ्तर से कई अहम दस्तावेज बरामद

मुंबई।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को मुंबई नदी सफाई प्रोजेक्ट में हुए 55 करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी की सिफारिशों पर इस योजना में धोखाधड़ी और अनियमितताओं की जांच कर रही थी। एफआईआर में पांच ठेकेदारों और तीन बीएमसी अफसरों को नामजद किया गया है, जिन पर फर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने और फंड में बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम देने का आरोप है। मंगलवार सुबह मुंबई के 8-9 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें आरोपी ठेकेदारों और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अफसरों के दफ्तरों और आवासीय परिसर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

छापे मारी में भुगतान रजिस्टर में गड़बड़ी और कार्यों के बिना निरीक्षण भुगतान। नदी सफाई के लिए फर्जी कंपनियों के जरिए ठेके जारी करना। काम पूरा होने से पहले बड़ी रकम का अग्रिम भुगतान के सबूत मिल हैं।

बीएमसी ने कहा है कि वह इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है।

बता दें मुंबई नदी सफाई प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की मीठी, पोइसर और दहिसर नदियों की सफाई कर उन्हें पुनर्जीवन देना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर पिछले कुछ समय से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यह घोटाला न केवल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

दिल्ली में बैठक में हुआ फैसला, 7 मई को देश के अधिकांश जिलों में होगी मॉक ड्रिल

नागरिकों को हमले से बचाने की दी जाएगी ट्रेनिंग, चेतावनी वाले बजेंगे सायरन

नई दिल्ली।

सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए। केंद्र सरकार ने 7 मई यानी बुधवार को देश के अधिकांश जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत को रूस से जंगी जहाज तमल भी मिल जाएगा। रूस 28 मई को इसे भारतीय नौसेना को सौंपेगा। यह जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत एलओसी पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए क्षेत्र को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हमले में 28 टूरिस्ट मारे गए थे। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार-सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही।

पहलगाम आतंकी हमला राजनीतिक रूप से किया गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं

सपा नेता ने दिया विवादित बयान, बीजेपी बोली- ये पाकिस्तान को दे रहे क्लीन चिट

लखनऊ।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में संभावित हमले की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के नेता लालबिहारी यादव ने पहलगाम हमले के लिए खुफिया विफलता पर सवाल उठा दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि यह अभी भी साफ नहीं हो सका है कि आतंकवादी हमला राजनीतिक रूप से किया गया या नहीं।

बता दें वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2019 का पुलवामा आतंकी हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया था या हमारे अपने लोगों द्वारा, यह अभी भी संदेह का विषय है। इसी तरह पहलगाम आतंकी हमला राजनीतिक रूप से किया गया था या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बीजेपी ने लालबिहारी यादव और विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी भाषा के बजाय पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष अपने बयानों से पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के बाद एक-एक करके कांग्रेस, आरजेडी और अब सपा नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। सपा नेता कह रहे हैं कि पहलगाम हमला राजनीतिक रूप से किया गया था। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

बीजेपी नेता ने दावा किया कि सपा के रामगोपाल यादव ने कहा था कि पुलवामा हमला वोट के लिए किया गया। इंडिया गठबंधन और पाकिस्तान दो अलग-अलग शरीर और एक आत्मा की तरह हैं। यूपीप के उपमुख्यमंत्री केपी मौर्य ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस और सपा को कौन सी बीमारी हो गई है...अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसी बातें कहता है, तो मैं यही कह सकता हूं कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है।

वहीं यूपी के मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि आपने सपा के कार्यकाल में प्रशासन देखा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और लूट थी। आज बीजेपी पिछले आठ सालों से सत्ता में है और राज्य में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ शांतिपूर्ण माहौल है...पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है।

जातीय पक्षपात पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला

छोटी जाति के जज की बर्खास्तगी से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।

न्यायपालिका में उपेक्षित समुदाय के जजों को भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की खंड पीठ ने पंजाब के एडिशनल सेशन जज की बर्खास्तगी के मामले में सुनवाई के दौरान कहा, जज को भी जातिगत पक्षपात का शिकार होना पड़ा। ऊंचे समुदाय के लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। झूठे आरोप में उसे बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जज की बर्खास्तगी को गलत मानते हुए जज को बहाल करने के आदेश दिए हैं। बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। उन्हें अमृतसर जिला कोर्ट में नियुक्त किया गया। इस दौरान दुष्कर्म के आरोप की शिकायत हाईकोर्ट में की गई। जब प्रेम कुमार वकालत करते थे। उसे वक्त उन्होंने दुष्कर्म पीड़ता की ओर से समझौते के लिए संपर्क कर पीड़ता को 1।50 लाख का मुआवजा दिलवाया था। इसकी शिकायत के आधार पर जज प्रेम कुमार की हाई कोर्ट द्वारा जांच कराई गई। उनकी ईमानदारी को संदिग्ध मानते हुए 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने शिकायत के आधार पर प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने निर्णय उनकी बर्खास्तगी को गलत बताते हुए जज की बहाली करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। ऊंचे समुदाय के लोग उपेक्षित समुदाय के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।

देश में जब एक जज के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है,कि आज भी देश में उपेक्षित वर्ग का किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है।

बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों की मुख्य सचिव सुधांश पंत ने समीक्षा की

जयपुर। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

सचिवालय में आयोजित बैठक में बुधवार, 7 मई को प्रस्तावित मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट हेतु संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संचार माध्यमों

एवं सायरनो को तुरंत दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, जल संसाधन एवं पीएचईडी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभागों के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभागों के शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, महानिदेशक इन्टेलिजेन्स, महानिदेशक गृह रक्षा, प्रबंध निदेशक, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंधक, उ.प. रेलवे जयपुर, कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद दल, ग्रुप कैप्टन, एयर फोर्स स्टेशन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, कमाण्डेंट छठी बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनसीसी निदेशक, जयपुर एयरपोर्ट निदेशक इत्यादि अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी अधिकारीगण ने बैठक में आपसी समन्वय से मॉक ड्रिल संपन्न करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की।

राजस्थान में 3 श्रेणियों में बांटे जिले

बता दें, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। मुख्य सचिव सुधांश पंत शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल की रणनीति पर चर्चा करेंगे।

1. सबसे संवेदनशील क्षेत्र-रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम भंडार के कारण

कोटा, रावतभाटा से निकटता और सामरिक महत्ता

2. मध्यम संवेदनशील क्षेत्र-इन जिलों में थल सेना, वायुसेना और अन्य सामरिक महत्व के प्रतिष्ठान हैं। जैसे- जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर, सीकर सहित 18 स्थान हैं।

3. कम संवेदनशील क्षेत्र-इसमें कुल 8 स्थान हैं, जहां खतरा कम लेकिन सतर्कता जरूरी मानी गई है। ये जगह फुलेरा, ब्यावर, जालौर, नागौर, पाली सहित कुल 8 स्थान हैं।

हमारी डबल इंजन सरकार राजस्थान में स्थापित कर रही विकास के नये कीर्तिमान-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में हमारी डबल इंजन सरकार विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है और वर्षों से लंबित कार्यों की राह प्रशस्त करने के साथ ही विकसित भारत-विकसित राजस्थांन के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

शर्मा मंगलवार को गुजरात के केवड़िया में आयोजित भाजपा सांसदों और विधायकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार गौरवशाली भारत का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद सुशासन से राजनीति की अवधारणा बदलकर राजनीतिक दलों और नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र देकर हमें जो मार्ग दिखाया है, वह भाजपा की कार्य संस्कृति का आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में पहले राष्ट्र हित फिर पार्टी हित और अंत में स्वहित आता है जबकि कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखकर काम करती है। उसने अपनी संस्कृति और विचारों को भी छोड़ दिया है।

शर्मा ने कहा कि यह प्रशिक्षण स्थल वह स्थान है जहां लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखण्डता और एकता की अलख जगाई थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण शिविर भाजपा के जनप्रतिनिधियों को नीति और रणनीति सिखाने के साथ ही नैतिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी सशक्त करेगा।

पानी और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम

शर्मा ने कहा कि प्रदेश को पानी और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए है। पानी की पर्याप्त

उपलब्धता के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ करने के साथ ही सोम-कमला-अंबा परियोजना, जवाई परियोजना व देवास परियोजना के विकास का काम हाथ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए हमने केंद्रीय पीएसयू के साथ 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू कर उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया है। राज्य में कुसुम के कम्पोनेन्ट-ए एवं कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। इस कारण हम लगभग 63 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली दे पा रहे हैं।

युवा एवं महिला कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो 37 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं, उनसे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के साथ ही निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। हमने प्रभावी कार्यवाही कर पेपरलीक के मामलों पर लगाम लगाई है।

शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने, लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर साढ़े छह हजार करने जैसे निर्णय भी लिए हैं।

अन्नदाता हो रहा खुशहाल, अन्त्योदय की भावना हुई साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने अन्नदाता के संबल के लिए राजस्थान में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 47 लाख किसानों को करीब 30 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये का बोनस देने एवं गेहूं दलहन तथा तिलहन की एमएसपी पर खरीद जैसे निर्णय भी किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना भी लागू की गई है। शर्मा ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के हित में लिए गए निर्णयों से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय का संकल्प साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 96 हजार से अधिक शहरी और ग्रामीण आवास बनाए जा चुके हैं तथा 5 लाख 48 हजार से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। हम गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में पहल करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर रहे हैं।

आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ बुनियादी सेवाओं का विस्तार

प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही बुनियादी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। हमारी सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल में 53 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने में 60 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में अटल पथ, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और ब्रिज निर्माण से सड़कों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के लिए इस राज्य बजट में 1,000 बसें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस

जिला कलक्टर की अपील-नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के दौरान घबराए नहीं, सक्रिय भागीदारी निभाएं

तैयारीयों को लेकर जिला स्तर पर समन्वय में बैठक आयोजित

सवाई माधोपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सभी जिलों के कलक्टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारत सरकार की ओर से बुधवार, 7 मई को प्रस्तावित मॉक ड्रिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला कलक्टर शुभम चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि भारत सरकार ने इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया है, जो प्रशासनिक, पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी आपात स्थिति में सुरक्षित व्यवहार सीखने का महत्वपूर्ण अवसर है।

जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने प्रस्तावित पूर्व अभ्यास के क्रम में मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों और मॉक ड्रिल के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना जिला स्तर पर समन्वय बैठक आयोजित

करके सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि वे 7 मई 2025 बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित हो रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा है कि सभी लोग इस अभ्यास का किसी भी आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा से संबंधित सबक सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें।

शुभम चौधरी ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर हवाई हमले की स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस क्रम में रात के समय ब्लैक आउट का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और विभागीय समन्वय की कसौटी पर खरा उतरने का पूर्वाभ्यास है, जिसमें गांव स्तर तक सभी लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

कलक्टर ने अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य न केवल आपदा के समय प्रशासन की तैयारियों को परखना है, बल्कि आम नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित करना भी है।

जिला कलक्टर ने कहा कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, हॉटलाइन/रेडियो लिंक, नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, ब्लैकआउट तैयारी, मेडिकल, रसद और अग्निशमन व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं का अभ्यास इस ड्रिल में किया जाएगा। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से विशेष रूप से इस गतिविधि में भाग लेने का आग्रह किया है ताकि आपदा की स्थिति में वे समाज के लिए मजबूत सहयोगी बन सकें।

सभी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और विभागीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस अभ्यास में अपनी जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और जिले को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्त बनाने में योगदान दें।

10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों का आपसी सहमति से होगा निस्तारण

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10 मई 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर) सहित जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों तथा अधीनस्थ तालुकाओं गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास पर स्थित न्यायालयों तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाड़ा में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय सहित अधीनस्थ तालुकाओं पर कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद, 138 एनआई एक्ट के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, गृहकर एवं नगरीय विकास कर के विवाद, शहरी जमाबंदी के विवाद, फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी

विवाद, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद, सभी प्रकार के राजस्व विवाद, भरण-पोषण एवं बालकों की अभिरक्षा से संबंधित विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, उपभोक्ता विवाद एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य विवादों तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 138 एनआई एक्ट के विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, उपभोक्ता एवं विक्रेता या सेवा प्रदाताओं के मध्य विवाद, कर संबंधी विवाद, रियल एस्टेट संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते से निस्तारण किया जावेगा।

आमजन से अपील है कि वे 10 मई को प्री-लिटीगेशन स्तर के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय स्तर पर एडीआर सेन्टर एवं संबंधित न्यायालयों में तथा तालुका स्तर पर गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास में स्थित न्यायालयों तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाड़ा में आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होवें।

11वीं राजस्थान ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2025 में राजदीप गुर्जर ने जीता स्वर्ण पदक

विशेष संवाददाता

गंगापुर सिटी। 11वीं राजस्थान ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2025 जयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई जिसमें राज्य के धौलपुर बीकानेर

,श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, चुरु, अजमेर आदि जिलों के लगभग 200 खिलाड़ियों ने नो-गी और गी-ग्रेपलिंग जैसे खेलों में अपनी स्पर्धा का प्रदर्शन किया एवं विभिन्न स्तर पर मेडल हासिल किये। इस प्रतिस्पर्धा में करौली जिले का नाम रोशन करते हुए खिलाड़ी राजदीप गुर्जर पुत्र श्री दयाराम गुर्जर निवासी खूबपूरा कुड़गांव ने ग्रेपलिंग के अंतर्गत अद्भुत प्रदर्शन करके राजस्थान स्तर पर स्वर्ण मेडल हासिल करके जिले व समस्त ग्रामवासी एवं परिवार का नाम रोशन किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए राजदीप ने बताया कि उनकी यह सफलता उनकी अकादमी के संचालक श्री हंसराज मीणा के निरंतर प्रयास एवं मेहनत के द्वारा ही यह संभव हो पाई है इसके लिए में समस्त परिवारजन एवं अकादमी के संचालक श्रीमान हंसराज मीणा जी का शुक्रगुजार हूं।

दबंगों ने पक्का निर्माण कर किया रास्ता अवरुद्ध

प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी नही हो रहा है समाधान

विशेष संवाददाता

करौली करौली जिले के कैलादेवी क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का मामला प्रकाश में आया है। वन्दे राजस्थान को मिली जानकारी के अनुसार कैलादेवी निवासी लीला देवी पत्नी गणेश प्रसाद शर्मा के घर में आने जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर दबंगों ने पक्का निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। जिसकी पीड़ित परिवार के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक करौली को 1 मई 2025 को मैं शिकायत परिवाद प्रस्तुत कर दिया इसके बाद भी अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही होती हुई नहीं दिख रही

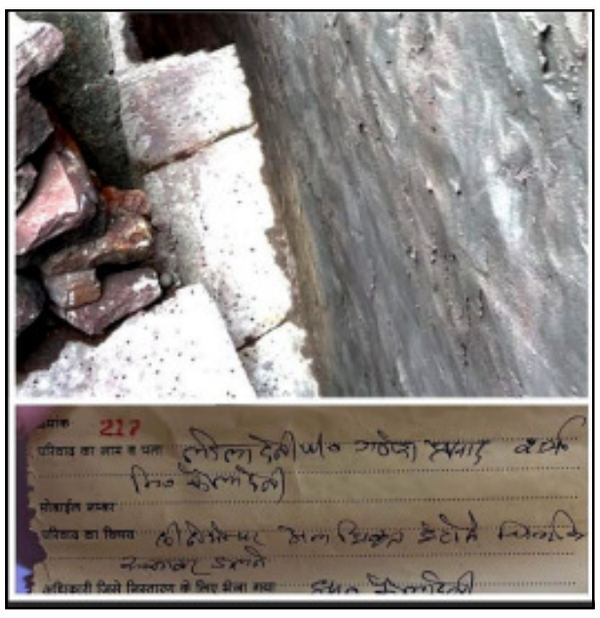

है। जबकि इस समय भाजपा सरकार में रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रदेश भर में शानदार कार्य किया जा रहा है जिससे वर्षों से बंद पड़े रास्ते खुलने से हजारों लोगों को अभी तक राहत मिल चुकी है और यह अभियान प्रदेशभर में निरंतर जारी है। लेकिन ऐसे समय में भी करौली जिले में दबंगों के द्वारा आमलोगों के रास्ते रोककर क्षेत्र में माहौल खराब किया जा रहा है। इसलिए करौली जिला पुलिस अधीक्षक को तुरन्त संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के आदेश जारी करने चाहिए।

कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं-चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा का बयान उनकी निराशा को दिखाता है। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है और न ही कोई विचार है। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, जनता के प्रति जवाबदेही, संवाद और जनहित के कार्यों को जमीन तक पहुंचाने पर जोर दिया जाता है।

सरकार में बैठे भाजपा नेता जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि राजस्थान सरकार के जनहित के कार्यों को और तेजी से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुजरात, जो कभी देश के लिए सुशासन का मॉडल था, वहां भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात ने सुशासन के क्षेत्र में मिसाल कायम की थी। चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि भाजपा में जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में भी ऐसे शिविर हो सकते हैं और अन्य राज्यों के लोग भी यहां प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि पार्टी के कार्यक्रमों का है। चतुर्वेदी ने डोटासरा से कहा कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717